

एन.एस.एन.पी.ल.माल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर।

राजरव विभाग

देहरादून : दिनांक : ०७ जनवरी, 2007

विषय: गै.0 गै.मी.फिको फूड्स प्रा०लि० को फूट एवं वेजीटेबुल कम्पोजिट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु तहसील गदरपुर के ग्राम पिपलिया में कुल 1.052 है० भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-35/सात-सा०गु०आ०/2006 दिनांक 04 अक्टूबर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय गै.0 गै.मी.फिको फूड्स प्रा०लि० को फूट एवं वेजीटेबुल कम्पोजिट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उप० जमींदारी विभांश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील गदरपुर के ग्राम पिपलिया में कुल 1.052 है० भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :-

- 1- केसा धारा 129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर यावेस में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर जैसी ही स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये आई होगा।
- 2- केसा बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि वचक या दृष्टि बधित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- केसा द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।
- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूजामी अनुरक्षित जनजाति के न हों और अनुरक्षित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से निम्नानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसका भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न

(4)

स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिये निर्धारित सिद्धान्तों/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

7- कय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग, यदि औद्योगिक से भिन्न हो, तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान राक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करने के पश्चात् ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल मूल के वेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

9- इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग फ्रूट एवं कम्पोजिट वेजीटेबुल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु किया जायेगा।

10- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिससे शासन खर्चित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

2- तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तदुद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

2- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।

3- सचिव, श्रम विभाग, उत्तरांचल शासन।

4- आयुक्त, कुर्गोऊ मण्डल, नैनीताल।

5- श्री मौख आहूजा, डायरेक्टर, मै0 मैग्नीफिको फूड्स प्रा0लि0, निवासी- गकान नं0-388, सेक्टर-15 फरीदाबाद, हरियाणा।

6- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।

7- माई फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।

020107011

020107011 102